



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 25 अगस्त, 2006/3 भाद्रपद, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 25 अगस्त, 2006

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्न. बिल/1-49/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 23) जो आज

दिनांक 25-8-2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाज़टा,
सचिव,

2006 का विधयेक संख्यांक 23

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें)
संशोधन विधयेक, 2006

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम,
2003 (2003 का 13) का संशोधन करने के लिए विधयेक ।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी संक्षिप्त नाम।
(वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2006 है ।

2. हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) के
2003 का 13 बृहत् नाम में "न्यायिक अधिकारियों के वेतन "शब्दों के पश्चात् ",भत्ते" चिन्ह
और शब्द अन्तः स्थापित किया जाएगा ।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 में कोष्ठक और शब्द "(वेतन" के
पश्चात् ",भत्ते" चिन्ह और शब्द अन्तः स्थापित किया जाएगा ।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 में विद्यमान खण्ड (क) को खण्ड (कक) धारा 2 का
के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड संशोधन ।
(कक) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (क) अन्तः स्थापित किया जाएगा,
अर्थात् :-

“(क) “भत्तों” से हिमाचल प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों को
31 जुलाई, 2006 को अनुज्ञेय भत्ते अभिप्रेत हैं;” ।

धारा 3 का
संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) शीर्षक में “वेतन” शब्द के पश्चात् “और भत्तों की दरें” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (2) अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(2) न्यायिक अधिकारियों के भत्तों की दरें और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।” ।

धारा 4
और 5 का
संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 4 और 5 में “वेतन” शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “वेतन, भत्ते” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 2003 हिमाचल प्रदेश राज्य में न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवा की शर्तों को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यद्यपि धारा 4 के फलस्वरूप राज्य सरकार, न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है और उक्त नियम बनाने की शक्तियों के प्रयोग में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। अब अस्पष्टता को दूर करने तथा राज्य में न्यायिक अधिकारियों के लिए भत्तों और उनकी अनुज्ञेयता की तारीख को अनुरक्षित रखने के दृष्टिगत पद "भत्तों" को स्पष्टतया अन्तः स्थापित करना समीचीन समझा गया है। इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,

मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख :2006.

वित्तीय ज्ञापन

न्यायिक अधिकारियों के भत्तों पर उपगत होने वाला कुल वार्षिक आवर्ती व्यय लगभग 21,29,140/- रुपये होगा जिसके अन्तर्गत पांच वर्ष में एक बार पाँच हजार रुपये की दर से दिया जाने वाला पोशाक भत्ता (रॉब अलाउंस) नहीं आएगा, जिसके लिए अनन्तिम रूप से 5,85,000/- रुपये का व्यय उपगत होगा। ये भत्ते पहले से ही दिए जा रहे हैं। इस प्रकार इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय विवक्षाएं नहीं होंगी।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 6 राज्य सरकार को न्यायिक अधिकारियों के भत्तों और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

**THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL OFFICERS (PAY AND CONDITIONS OF SERVICE)
AMENDMENT BILL, 2006**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act, 2003 (Act No. 13 of 2003).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Amendment Act, 2006.

Amendment
of long
title.

2. In long title of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act, 2003 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after the words "regulation of the pay", the sign and word ", allowances" shall be inserted. 13 of 2003.

Amendment
of section 1.

3. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), after the bracket and word "(Pay", the sign and word ", Allowances" shall be inserted.

Amendment
of section 2.

4. In section 2 of the principal Act, existing clause (a) shall be renumbered as clause (aa) and before clause (aa) as so renumbered, the following new clause (a) shall be inserted, namely:—

"(a) "Allowances" means the allowances admissible to the Judicial Officers in Himachal Pradesh on 31st July, 2006;"

Amendment
of section 3.

5. In section 3 of the principal Act,—

- (a) in the heading, after the word "Salaries", the words "and rates of allowances" shall be inserted; and
(b) after sub-section (1), the following sub-section (2) shall be inserted, namely:—

"(2) The rates of allowances and other conditions of services of the Judicial Officers shall be such as may be prescribed."

Amendment
of sections 4
and 5.

6. In sections 4 and 5 of the principal Act, for the word "pay" wherever it occurs, the words and sign "pay, allowances" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act, 2003 was enacted for regulating the pay and service conditions of the Judicial Officers in the State of Himachal Pradesh and for the matters connected therewith or incidental thereto. Though by virtue of section 4, the State Government has been empowered to make rules for regulating the pay and conditions of service of the Judicial Officers and in exercise of the said rule making powers, rules have been framed to regulate the recruitment and conditions of service of Judicial Officers. Now, it is considered expedient to explicitly insert the term "Allowances" in the Act *ibid*, with a view to remove the ambiguity and further preserving the date of allowances and their admissibility to the Judicial Officers in the State. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:

The.....2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

The total annual recurring expenditure being incurred on allowances of the Judicial Officers will be approximately Rs. 21,29,140/- excluding the Robe Allowances @ Rs. 5,000/- once in five years for which a tentative expenditure of Rs. 5,85,000/- will be incurred. These allowances are already being given. As such, there will be no additional financial implications.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 6 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules regulating the allowances and conditions of service of the Judicial Officers. This delegation is essential and normal in character.

